साउथ एशिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड.

बनाम

अनुभाग.बी. सरूप सिंह और अन्य

18-01-1965

(के. सुब्बा राव, रघुवर दयाल, आर.अनुभाग. बछावत, वी. रामास्वामी)

लाहौर उच्च न्यायालय के लिए पत्र पेटेंट। सीएलअनुभाग. 10, 11-दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 59), अनुभागअनुभाग. 39,43- एकल न्यायाधीश के निर्णय-पत्र पेटेंट के तहत अपील-चाहे विधान मंडल द्वारा छीन लिया गयी हो -अन्तिम का अर्थ-किसी कानून के तहत अपील यदि पत्र पेटेंट अपील शामिल है।

प्रार्थीगण ने बेदखली के लिए अंतर्गत धारा 14 दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत अपीलांट के विरूद्ध नियंत्रक के समझ एक आवेदन पेष किया। नियंत्रक ने उक्त याचिका स्वीकार की और किराया नियंत्रण अधिकरण द्वारा याचिका स्वीकार की और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील किराया नियंत्रण अधिकरण द्वारा अपील खारिज की जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 39 के तहत उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की यह द्वितीय अपील एकल न्यायाधीष द्वारा खारिज की गई और अन्य अपील अंतर्गत क्लाज 10 लेटरर्स पेटेन्ट्स खंडपीठ के सामने निस्तारण हेतु पेश हुई यह संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की गई।

अपील में आयोजित:

(i) उच्च न्यायालय में अपील को विनियमित किया जाएगा उच्च न्यायालय में अभ्यास और प्रक्रिया प्राप्त करना। अभ्यास में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अनुभाग 108 के तहत इसे प्रदत्त शक्तियां, अनुभाग. 39 के तहत एक अपील दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी । उक्त अपील में एकल जज द्वारा दिया गया कोई भी आर्डर, सीएल 10 लेटर्स पेटेंट के तहत होगा, उस न्यायालय में अपील के अधीन होगा। यदि एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश एक निर्णय है और यदि उपयुक्त विधान मंडल के पास स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से है निहितार्थ ने अपील का अधिकार नहीं छीना, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अपील सीएल 10 लेटर्स पेटेंट के तहत उच्च न्यायालय को एकल न्यायाधीश के निर्णय से होगी. 765 D-E]

नेशनल सिलाई थ्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चैडविक एंड ब्रदर्स। लिमिटेड [1953] अनुभाग.सी.आर. 1028, नेशनल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड बनाम पोस्टमास्टर-जनरल (1913) ए.सी. 546, आर.एम.ए.आर.ए. आदिकप्पा चेट्टियार बनाम रा. चन्द्रशेखर थेवर, (1947) आ.ईए. 264, भारत के राज्य सचिव बनाम चेल्ली कनिल रामा राव, (1916) आई.एल.आर. 39 मद्रास 617, माउंग बा थाव बनाम मा पिन, (1934)

एल.आर. 61 आई.ए. 158 एवं हेम सिंह बनाम बसंत दास, ए.आई.आर. 1936 पी.सी. 93, पर भरोसा किया।

(ii) अभिव्यक्ति "अंतिम" का एक प्रतिबंधात्मक अर्थ हो सकता है अन्य संदर्भों में, लेकिन अनुभाग. 43 में अधिनियम, जैसे प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता और यह इंगित करता है कि ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अपील पर पारित आदेश के विरुद्ध आगे अपील करने पर विचार नहीं किया गया है. [766 जी-एच; 768 बी]

माउंग बा थाव बनाम मा पिन, (1934) एल.आर. 61 आई.ए. 158, किड बनाम लिवरपूल वॉच कमेटी, (1908) ए.सी. 327 और सचिव राज्य बनाम हिंदुस्तान सहकारी बीमा सोसायटी लिमिटेड. ए.आई.आर. 1931 पी.सी. 149 का उल्लेख है।

(iii) अनुभाग की धारा 39(1) के तहत एक अपील और एक अपील सीएल 10 लेटर्स पेटेंट के तहत एक अपील का हिस्सा नहीं बनते हैं। अपीलें कानून में वास्तव में अलग हैं --एक क़ानून द्वारा दी गई और दूसरी पत्र पेटेंट द्वारा दी गई । अनुभाग में अभिव्यक्ति "अपील" अधिनियम की धारा 39 में अभिव्यक्ति अपील, पत्र पेटेंट के खंड 10 के तहत एक पत्र पेटेंट अपील में नहीं आती है [769 एफ-एच]757

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहिंदरा सप्लाई कंपनी, [1962] 3 एस.सी.आर. 497 और लाडली प्रसाद जयसवाल बनाम करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड। [1964] 1 एस.सी.आर. 270, पर भरोसा किया।

राधा मोहन पाठक बनाम उपेन्द्र पटोवारी, ए.आई.आर. 1962 असम 71 और हंसकुमार किशनचंद बनाम भारत संघ, [1959] एस.सी.आर. 1177, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 726/1964।

पंजाब उच्च न्यायालय के अपील संख्या 85-डी/1963 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.12. 1963 से उत्पन्न।

ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, वेद व्यास, पी. एन. चड्ढा, एस.के. मेहता और के. एल. मेहता। अपीलकर्ता के लिए

गोपाल सिंह, उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के लिए।

गुरचरण सिंह बख्शी और गोपाल सिंह, उत्तरदाताओं संख्या 3 से 5 के लिए।

सुब्बा राव, न्यायाधिपति -

प्रमाण पत्र द्वारा यह अपील यह प्रश्न उठाती है कि क्या लाहौर उच्च न्यायालय के लिए पत्र पॉलिटिक्स के खंड 10 के तहत पंजाब न्यायालय की एक डिवीजन बेंच में एकल न्यायाधीश द्वारा नियुक्त निर्णय के विरुद्ध

अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली कंट्रोल स्पीकर अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 39 के तहत दूसरी अपील में कहा, जिसके बाद यह अधिनियम कहा जाएगा।

उठाए गए प्रश्न से संबंधित तथ्य संक्षेप में बताए जा सकते हैं। प्रतिवादी प्लॉट नंबर 5, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली के मालिक हैं। मेसर्स एलन बेरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 1 मार्च, 1956 के लीज डीड के तहत इसका पट्टा लिया। मेसर्स एलन बेरी एंड कंपनी ने उक्त लीज डीड के तहत अपना हित साउथ एशिया इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड को सौंप दिया, यहां अपीलकर्ता। इसके बाद, उत्तरदाताओं ने अधिनियम की धारा 14 के तहत नियंत्रक, दिल्ली के समक्ष अपीलकर्ता को उक्त परिसर से इस आधार पर बेदखल करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि मेसर्स एलन बेरी एंड कंपनी ने अनाधिकृत रूप से उक्त परिसर को उसके पक्ष में सौंपा था। अपीलकर्ता नियंत्रक ने अपने आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 1962 द्वारा याचिका स्वीकार कर ली। 23 जनवरी, 1963 को, उक्त आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, दिल्ली द्वारा खारिज कर दी गई थी। ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 39 के तहत पंजाब उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उक्त दूसरी अपील 10 मई, 1963 को हरबंस सिंह, जे द्वारा खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 10 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उक्त उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में

अपील दायर की थी। वह अपील उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष निपटान के लिए आई, जिसने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री ए. विश्वनाथ शास्त्री ने हमारे सामने निम्नलिखित बिंदु उठाए:

(1) अधिनियम की धारा 39 किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है और इसलिए, जब एक बार वह अपील उच्च न्यायालय में पहुँचती है, तो उसे उसी तरह से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना होता है जैसे वह अन्य अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है, यानी उस अपील में एकल न्यायाधीश का निर्णय खंड के तहत उच्च न्यायालय में अपील के अधीन हो जाता है। 10 पत्र पेटेंट.

(2) अधिनियम की धारा 43 केवल ट्रिब्यूनल के आदेश पर सवाल उठाने के उद्देश्य से संपार्श्विक कार्यवाही शुरू करने पर रोक है और यह अधिनियम की धारा 39 के तहत अपील में एकल न्यायाधीश के फैसले को अंतिम नहीं बनाती है; और, इसके अलावा, एक पत्र पेटेंट अपील उच्च न्यायालय में एक अलग अपील नहीं है, बल्कि वास्तव में, उच्च न्यायालय में उसी अपील की निरंतरता है।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील गोपाल सिंह और गुरचरण सिंह बख्शी को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है: अधिनियम अपील पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को एक विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करता है; और ऐसी अपील में निर्णय लेटर्स पेटेंट के खंड 10 पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 का पहला भाग, जिस पर अपीलकर्ता भरोसा करता है, केवल उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील का प्रावधान करता है; और भले ही अपीलीय क्षेत्राधिकार में दिए गए निर्णय को समझने के लिए पर्याप्त व्यापक हो, फिर भी यह न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील होनी चाहिए। वर्तमान मामले में अधिनियम के तहत कार्य करने वाला ट्रिब्यूनल एक न्यायालय नहीं है और इसलिए, ऐसे ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय उक्त खंड के तहत लेटर्स पेटेंट अपील के अधीन नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से, अधिनियम की धारा 43 अपील में किए गए एकल न्यायाधीश के फैसले को अंतिम बनाती है और इसलिए, उस सीमा तक, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 को उपयुक्त विधानमंडल द्वारा संशोधित किया गया है।

आइए सबसे पहले न्यायिक निर्णयों से अप्रभावित प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करें। इस स्तर पर पंजाब उच्च न्यायालय को संचालित करने वाले लेटर्स पेटेंट के भौतिक प्रावधानों को पढ़ना सुविधाजनक होगा।

खंड 11. और हम यह भी निर्धारित करते हैं कि लाहौर में उच्च न्यायालय पंजाब और दिल्ली प्रांतों के सिविल न्यायालयों और इसके अधीक्षण के अधीन अन्य सभी न्यायालयों से अपील की अदालत होगी, और अपील का कार्य करेगी। ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार, जो इन प्रस्तुतियों के प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले, उस समय लागू किसी भी कानून के आधार पर पंजाब के मुख्य न्यायालय में अपील के अधीन थे, या उस तारीख के बाद उच्च न्यायालय में अपील के अधीन घोषित किए जा सकते थे। भारत के लिए सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा लाहौर में न्यायिक न्यायालय।

खंड 10, 1928 के लेटर्स पेटेंट द्वारा संशोधन से पहले, इस प्रकार पढ़ा गया:

> "और हम यह भी तय करते हैं कि फैसले के खिलाफ अपील लाहौर के उक्त उच्च न्यायालय में की जाएगी (जो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अभ्यास में दिया गया आदेश नहीं है और जो सजा या आदेश के अभ्यास में पारित या दिया गया आदेश नहीं है) भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 107 के प्रावधानों के तहत या आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी डिवीजन कोर्ट के एक न्यायाधीश की अधीक्षण की शक्ति, उक्त की

धारा 13 के अनुसार सुनाया गया अधिनियम, और यह कि उक्त उच्च न्यायालय के दो या दो से अधिक न्यायाधीशों या ऐसे डिवीजन कोर्ट के फैसले (जैसा कि पूर्वोक्त कोई सजा या आदेश नहीं है) के खिलाफ उक्त उच्च न्यायालय में अपील भी की जाएगी, जब भी ऐसे न्यायाधीश समान रूप से हों राय में विभाजित है, और उस समय उक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या के बहुमत के बराबर नहीं है; लेकिन उक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अन्य निर्णयों के खिलाफ अपील करने का अधिकार, या ऐसा डिवीजन कोर्ट, हमारे या उनके प्रिवी काउंसिल में हमारे, हमारे उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकारियों के लिए होगा, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।"

1928 में संशोधन के बाद, खंड 10 में लिखा है:

"और हम यह भी तय करते हैं कि फैसले के खिलाफ लाहौर स्थित न्यायिक उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी (अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में पारित निर्णय नहीं है) एक न्यायालय, जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन है, और पुनरीक्षण

क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया आदेश नहीं है, और धारा के प्रावधानों के तहत अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग में पारित या दिया गया एक वाक्य या आदेश नहीं है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 107, या आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में) उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी डिवीजन कोर्ट के एक न्यायाधीश की, भारत सरकार अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में, और इससे पहले कुछ भी प्रदान किए जाने के बावजूद भारत सरकार अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, फरवरी 1929 के पहले दिन या उसके बाद दिए गए उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी डिवीजन कोर्ट के एक न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील उक्त उच्च न्यायालय में की जाएगी। उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जहां निर्णय पारित करने वाला न्यायाधीश घोषणा करता है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है। ; लेकिन उक्त उच्च न्यायालय या ऐसे डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीशों के अन्य निर्णयों के खिलाफ अपील का अधिकार हमें, हमारे उत्तराधिकारियों या हमारे या उनके प्रिवी काउंसिल के

उत्तराधिकारियों को होगा, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।"

लेटर्स पेटेंट के खंड 11 के पहले भाग में कहा गया है कि उच्च न्यायालय पंजाब और दिल्ली प्रांतों की सिविल अदालतों और उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन अन्य सभी न्यायालयों से अपील का न्यायालय होगा; इसका दूसरा भाग उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है जो लेटर्स पेटेंट के प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले थे, जो उस समय लागू किसी भी कानून के आधार पर या उसके बाद पंजाब के मुख्य न्यायालय में अपील के अधीन थे। उस तारीख को भारत के लिए सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा लाहौर के उच्च न्यायालय में अपील के अधीन घोषित किया जाएगा। दूसरा भाग न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, जो न्यायालय नहीं हैं, पर अपीलीय क्षेत्राधिकार के बीच अंतर नहीं करता है। यदि किसी सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून किसी मामले को उच्च न्यायालय में अपील के अधीन घोषित करता है, तो उक्त उच्च न्यायालय उस पर विचार करने और कानून के अनुसार उसका निपटान करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लेता है। यदि उच्च न्यायालय लेटर्स पेटेंट के खंड 11 के संदर्भ में किसी अपील पर विचार करता है, तो उसका खंड 10 ऐसी अपील के लिए आकर्षित होता है। भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 के तहत, उच्च न्यायालय अपने स्वयं के नियमों द्वारा,

जैसा वह उचित समझे, एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा या उच्च न्यायालय के दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा गठित खंड न्यायालय गठन कर सकता है। न्यायालय में निहित मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार; और उसके खंड (2) के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह निर्धारित करेंगे कि प्रत्येक मामले में न्यायाधीश को अकेले बैठना है, और न्यायालय के न्यायाधीशों को, चाहे मुख्य न्यायाधीश के साथ या उसके बिना, कई डिवीजन न्यायालयों का गठन करना है। यदि भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील उस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाती है और उस न्यायाधीश द्वारा निर्णय सुनाया जाता है, तो उसको यह देखना होगा लेटर्स पेरेंट का खंड 10 क्या उक्त निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में आगे अपील की जा सकती है। 1928 में लेटर्स पेटेंट के खंड 10 में संशोधन से पहले, उक्त उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश या किसी डिवीजन कोर्ट के एक न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उक्त उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी; लेकिन उस नियम के कुछ अपवाद भी थे। यदि निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 107 के तहत अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए या आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था, तो उसके फैसले के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जा सकती।

इसके अलावा कोई अपवाद नहीं था जैसे कि उक्त निर्णय किसी

न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में होना चाहिए था। उक्त खंड को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि अपवर्जित तीन मामलों को छोड़कर, किसी अन्य क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसा कि तब खंड खड़ा था, ऐसा प्रतीत होता है कि अपील बिना किसी अवधि के द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ की जा सकती है। 1928 में किए गए संशोधन का प्रभाव, जहां तक वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक है, दूसरी अपील में बैठे एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय से अपील के अधिकार का समाप्त है जब तक कि निर्णय पारित करने वाला न्यायाधीश एक प्रमाण पत्र नहीं देता है मामला अपील के लिए उपयुक्त है। संशोधित खंड, संभवतः कलात्मक प्रारूपण के उद्देश्य से, व्यावहारिक रूप से पहले भाग को वैसा ही छोड़ देता है जैसा वह था और दूसरे भाग में ऐसे एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आगे अपील के मामले में एक सीमा पेश की जाती है। अपवादों को छोड़कर संशोधित उपवाक्य के भाग को देखने से यह स्पष्ट है कि इसकी शब्दावली सामान्य है। इसके तहत उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, चाहे उक्त निर्णय अपीलीय, पुनरीक्षण या आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किया गया हो या जहां निर्णय किसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ पहली अपील या दूसरी अपील में किया गया हो। या एक

न्यायाधिकरण. सामान्य नियम से चार अपवाद निकाले गए हैं। असंशोधित खंड के संदर्भ में पहले से ही देखे गए सामान्य नियम के तीन अपवादों के अलावा, संशोधित खंड पूर्व में देखे गए एक और अपवाद का परिचय देता है। इसका परिणाम यह है कि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के पहले भाग के तहत अपील अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में या प्रथम अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले से होती है, चाहे अपील इसके खिलाफ हो न्यायालय का आदेश है या नहीं; और द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार के मामले में, यदि अपील किसी न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध है, जो न्यायालय नहीं है। लेकिन उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री या आदेश के खिलाफ दूसरी अपील में दिए गए फैसले के मामले में, कोई भी आगे अपील नहीं की जा सकती जब तक कि उक्त न्यायाधीश यह घोषित न कर दे कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है। संरचना द्वारा, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के प्रावधानों की व्यापकता के दायरे को प्रतिबंधित करना स्वीकार्य नहीं है। तर्क यह है कि सीएलएस का एक संयुक्त वाचन। लेटर्स पेटेंट के भाग 10 और 11 इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खंड 10 का पहला भाग भी केवल उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलों से संबंधित है, इस तर्क में कोई बल नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया है, खंड 11 एक न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध एक उपयुक्त विधानमंडल द्वारा उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करने पर विचार करता है।

"उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय" शब्दों की व्यापकता से अलग होने के बजाय, खंड 11 इंगित करता है कि उक्त निर्णय एक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में लिया गया है। यह कुछ बल के साथ कहा जाता है कि यदि इस संरचना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक विसंगति होगी, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने डिक्री के संबंध में अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, उस न्यायालय में आगे अपील तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उक्त न्यायाधीश यह घोषित न कर दे कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है, जबकि, यदि अपने दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उसने ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील में कोई निर्णय पारित किया है, तो मामले को उक्त उच्च न्यायालय में आगे की अपील पर ले जाने के लिए ऐसी कोई घोषणा आवश्यक नहीं है। यदि विधायिका का स्पष्ट इरादा स्पष्ट है, तो उन संभावित कारणों पर अटकलें लगाने की अनुमति नहीं है, जिन्होंने विधायिका को मामलों के दो वर्गों के बीच अंतर करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, विधायिका ने उस मामले में एक सीमा लगाना उचित समझा जहां 3 न्यायालयों ने निर्णय दिया, जबकि उसने उस मामले में एक सीमा लगाने के बारे में सोचना उचित नहीं समझा जहां केवल एक न्यायालय ने निर्णय दिया।

यह न्यायालय मैंनेशनल सिलाई धागा कंपनी लिमिटेड बनाम। जेम्स चैडविक एंड ब्रदर्स लिमिटेड (जे. एंड पी. कोट्स लिमिटेड, असाइनी),, बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट के खंड 15 को लाहौर उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अनुरूप माना गया। वहां सवाल यह था कि क्या लेटर्स पेटेंट अपील ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1940 के तहत ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले से लेकर उस हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच तक हो सकती है। धारा 76(1) उक्त अधिनियम में प्रावधान है कि

> "इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत रजिस्ट्रार के किसी भी निर्णय के खिलाफ अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी"

और अधिनियम में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अपील में उच्च न्यायालय द्वारा, या अपील में पारित आदेश अपील योग्य था या नहीं। इस न्यायालय के समक्ष दो बिंदु उठाए गए थे,

(1) बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के पहले भाग के प्रावधानों के तहत ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 76 के तहत उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। और

(2) उक्त खंड उस मामले में लागू नहीं होगा जहां यह नहीं कहा जा सकता कि निर्णय भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 के अनुसार दिया गया है। पहले प्रश्न पर, इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1940 की धारा 76 द्वारा प्रदत्त अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में जब्त किए जाने पर, उसे उस क्षेत्राधिकार का उसी तरह प्रयोग करना था जैसे वह अपने अन्य अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है और जब ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाना था, तो उसका निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत अपील का विषय बन गया, क्योंकि ट्रेड मार्क्स अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी नहीं है। दूसरे प्रश्न पर, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "इसलिए हमारी राय है कि भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108, उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है जिसे वह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में समय-समय पर उच्च न्यायालय से प्रयोग कर सकता है, चाहे वह सरकार के लागू होने पर मौजूद हो। भारत का अधिनियम, 1915, या किसी बाद के कानून द्वारा इसे प्रदान किया गया है।"

उस मामले और वर्तमान मामले के बीच अंतर यह है कि उस मामले में एकल न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ पहली अपील में

एक निर्णय पारित किया, जबकि वर्तमान मामले में एकल न्यायाधीश ने दूसरी अपील में एक आदेश पारित किया। लेकिन इससे लाहौर उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के हिस्से के संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के अनुरूप है। एक अन्य अंतर यह है कि लाहौर उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट के खंड 11 के अंतिम भाग के तहत शब्द हैं

> "या उसके बाद की तारीख को किसी भी कानून द्वारा लाहौर में न्यायिक उच्च न्यायालय में अपील के अधीन घोषित किया जा सकता है।" भारत के लिए सक्षम विधायी प्राधिकारी",

उक्त शब्द बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट के संबंधित खंड 16 में अनुपस्थित हैं। उक्त चूक के बावजूद इस न्यायालय ने उक्त मामले में माना कि ट्रेड मार्क्स अधिनियम के तहत अपील उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही प्रयोग किए जा रहे अपीलीय क्षेत्राधिकार के लिए अपील की एक नई विषय-वस्तु का एक अतिरिक्त था और धारा 108 के तहत बनाए गए नियम भारत सरकार अधिनियम, 1915, उसी पर लागू होता है। यह तर्क दिया गया है कि उस मामले में यह तर्क नहीं दिया गया था कि रजिस्ट्रार एक न्यायालय नहीं था, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि रजिस्ट्रार एक न्यायालय था और उस धारणा पर यह माना गया कि बॉम्बे

के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 का पहला भाग उच्च न्यायालय आकर्षित हुआ. हमें इस तर्क का कोई औचित्य नजर नहीं आता. न्यायालय के समक्ष उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि ट्रेड मार्क्स अधिनियम ने एक नया न्यायाधिकरण बनाया और उच्च न्यायालय को एक नया अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया। इस न्यायालय ने उस तर्क को निम्नलिखित शब्दों के साथ खारिज कर दिया:

> "क़ानून इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए और अधिनियम द्वारा बनाए गए अधिकारों को प्रभावी करने के लिए रजिस्ट्रार को एक न्यायाधिकरण बनाता है और उच्च न्यायालय को इस न्यायाधिकरण के निर्णयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार दिए बिना दिया गया है।"

पूरा निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ा कि रजिस्ट्रार केवल एक न्यायाधिकरण है। यह कल्पना करना संभव नहीं है कि इस न्यायालय के अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों दोनों ने इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया कि न्यायाधिकरण एक न्यायालय नहीं था और इसलिए, उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के पहले भाग को लागू किया। दरअसल, उस मामले में अपील पर भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 की प्रयोज्यता का सवाल ही नहीं उठता अगर यह सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील होती। इसलिए, हम इस तर्क को स्वीकार नहीं

कर सकते कि इस न्यायालय ने माना कि उस मामले में अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 को लागू करने में रजिस्ट्रार एक न्यायालय था। इसलिए यह निर्णय हमारे सामने अब उठे प्रश्न को कवर करता है।

वर्तमान मामले पर लागू प्रासंगिक नियम इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में इस प्रकार बताया गया है;

> "स्पष्ट रूप से अपील उच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद इसे उस न्यायालय के कार्यप्रणाली के नियमों के अनुसार और उस चार्टर के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके तहत उस न्यायालय का गठन किया गया है और उस क्षेत्राधिकार का उपयोग करने की विधि और तरीका जो उसे इसके संबंध में शक्ति प्रदान करता है। नियम अच्छी तरह से स्थापित है कि जब कोई क़ानून निर्देश देता है कि अपील पहले से स्थापित न्यायालय में की जाएगी, तो अपील को उस न्यायालय के कार्यप्रणाली द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।"

यह सिद्धांत न्यायिक समिति द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित किया गया था: नेशनल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड बनाम पोस्टमास्टर-जनरल [1913] एसी 546 देखें; RMARA अडैकप्पा चेट्टियार बनाम रा. चन्द्रशेखर

थेवर[1947] 74 आईए 264.; भारत के राज्य सचिव बनाम चेल्लिकानि रामा राव ।LR1916। पागल। 617; माउंग बा थाव बनाम मा पिन एल.आर (1934) 61 इंडैप 158.) और हेम सिंह बनाम बसंत दास एआईआर 1936 93 (प्रिवी काउंसिल)

उक्त चर्चा से निम्नलिखित कानूनी स्थिति उभरती है: एक क़ानून किसी ट्रिब्यूनल या न्यायालय के आदेश से बिना किसी प्रतिबंध के उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दे सकता है। उच्च न्यायालय में अपील को उच्च न्यायालय में प्राप्त कार्यप्रणाली द्वारा विनियमित किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, अधिनियम की धारा 39 के तहत एक अपील की सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। उक्त अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत, उस न्यायालय में अपील के अधीन होगा। यदि एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश एक निर्णय है और यदि सक्षम विधानमंडल ने, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, अपील का अधिकार नहीं छीना है, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि खंड के तहत एकल न्यायाधीश के निर्णय से अपील की जाएगी। उच्च न्यायालय को पत्र पेटेंट के 10. इसका तात्पर्य यह है कि, यदि अधिनियम ने लेटर्स पेटेंट अपील को दूर नहीं किया होता, तो अपील

निश्चित रूप से एकल न्यायाधीश के फैसले से लेकर उच्च न्यायालय तक होती।

हमने जो विचार व्यक्त किया है, उसमें इस सवाल पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि ट्रिब्यूनल एक अदालत है या नहीं, क्योंकि, जैसा कि हमने पहले बताया है, यह लेटर्स पेटेंट अपील की रखरखाव के सवाल से संबंधित नहीं है।

अगला प्रश्न यह है कि क्या लेटर्स पेटेंट, लाहौर के खंड 10 द्वारा प्रदत्त अपील का अधिकार उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा छीन लिया गया है। यह माना जाता है कि सक्षम विधानमंडल उस अधिकार को छीन सकता है: लेटर्स पेटेंट, लाहौर का खंड 37 देखें। प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 43 का यह प्रभाव है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर अब ध्यान दिये जा सकने योग्य है ।

धारा 39.

(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई अपील नहीं की जाएगी, जब तक कि अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो।

धारा 43. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, नियंत्रक द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश या इस अधिनियम के तहत अपील पर पारित आदेश अंतिम होगा और किसी भी मूल मुकदमे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

उक्त दो धाराओ का एक संयुक्त वाचन करने पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील के अधिकार के अधीन, अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम है और किसी भी मूल मुकदमे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में इसे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। श्री विश्वनाथ शास्त्री का तर्क है कि अधिनियम की धारा 43 के अंतिम वाक्य में "अंतिम" को अभिव्यक्त करता है। उनके अनुसार, अंतिमता केवल संपार्श्विक कार्यवाहियों, जैसे मुकदमे, आवेदन और निष्पादन कार्यवाही के संदर्भ में है।

अभिव्यक्ति "अंतिम" प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि अधिनियम के तहत अपील पर पारित आदेश निश्चयात्मक है और इसके खिलाफ कोई और अपील नहीं होगी। हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 43 में अंतिम वाक्य, उक्त अभिव्यक्ति के दायरे को प्रतिबंधित नहीं करता है; वास्तव में, उक्त वाक्य एक और प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम की धारा 43 के पहले भाग में अभिव्यक्ति "अंतिम" आगे की अपील को समाप्त कर देती है और शब्द "किसी भी मूल मुकदमे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्न नहीं

उठाया जाएगा" शब्द संपार्श्विक कार्यवाही पर रोक लगाते हैं। यह धारा पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। अपील में निर्णय की सत्यता पर अपील के माध्यम से या संपार्श्विक कार्यवाही के माध्यम से सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह सच है कि अभिव्यक्ति "अंतिम" का अन्य संदर्भों में प्रतिबंधात्मक अर्थ हो सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 43 के लिए ऐसा प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम का अध्याय VI इसके तहत उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम का प्रावधान करता है। अधिनियम एक स्व-निहित है और विधानमंडल का इरादा अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली अपीलों के निपटाने के लिए एक विस्तृत कोड प्रदान करना था। अधिनियम की धारा 43 के शुरुआती शब्द "इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर" इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अधिनियम के बाहर किसी चीज का सहारा लेकर आदेश की अंतिमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। "अंतिम" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने वाले बाद में उद्धृत कुछ निर्णयों को उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता है। माउंग बा थाव बनाम मा पिन में न्यायिक समिति को इस बात पर विचार करना था कि क्या एपीएल.आर(1934).61 इंडएपी 158 अपील प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 की धारा 75(2) के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में दायर की गई थी। अधिनियम, 1920। उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के

अधीन और किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, अधिनियम के तहत जिला न्यायालय का निर्णय अंतिम था; लेकिन धारा 75(2) के तहत, जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार था। न्यायिक समिति ने माना कि ऐसे मामले में जहां अधिनियम उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत और उसके अधीन प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है। इसने इस सिद्धांत को दोहराया कि जहां किसी न्यायालय को देश के सामान्य न्यायालयों में से एक के रूप में अपील की जाती है, वहां सीपीसी के सामान्य नियम लागू होते हैं। यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि जिला न्यायालय का आदेश उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अंतिम था और उक्त अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय को अपील का अधिकार दिया गया था। अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को अंतिम नहीं बनाया गया। इसलिए, न्यायिक समिति ने माना कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। इसलिए, यह निर्णय वास्तव में अपीलकर्ता की मदद नहीं करता है। किड बनाम लिवरपूल वॉच कमेटी एलआर(1934) 61 इंडएपी 158 में तथ्य इस प्रकार थे: पुलिस अधिनियम, 1890 की धारा 11 (53 और 54 विक्ट. सी. 45) के तहत, एक कांस्टेबल की पेंशन की राशि के संबंध में तिमाही सत्र में अपील की गई थी। तिमाही सत्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया था:

"वह न्यायालय, मामले की जांच के बाद, मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो न्यायालय को उचित लगे, जो आदेश अंतिम होगा।"

लॉर्ड लोरबर्न, एलसी ने उक्त अनुभाग की व्याख्या इस प्रकार की:

"जहां यह कहता है कि, ऐसे आदेश के बारे में बोलते हुए, कि यही अंतिम होगा तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि तीन सत्रों में मामले का अंत होना है..."।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड (1934) एलआर 61 इंडएपी 158 में न्यायिक समिति ने फिर से संरचना को "अंतिम" माना और माना कि विधायका का आशय किसी भी आगे की अपील को बाहर करना था। कलकत्ता सुधार अधिनियम, 1911 की धारा 71 के तहत, ट्रिब्यूनल के एक अवार्ड से उच्च न्यायालय में अपील का एक सीमित अधिकार दिया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि, केवल उस अधिकार के अधीन, अवार्ड अंतिम होना चाहिए। अंतिमता के प्रावधान का उद्देश्य किसी भी आगे की अपील को बाहर करना था। किसी और उद्धरण की आवश्यकता नहीं है. जैसा कि हमने कहा है, अधिनियम की धारा 43 में अंकित "अंतिम" इंगित करती है कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील पर पारित आदेश के खिलाफ कोई और अपील करने पर विचार नहीं किया गया है।

इस संरचना से बचने के लिए "उच्च न्यायालय में अपील" अभिव्यक्ति को एक बड़ा दायरा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि अधिनियम की धारा 43 और 39 में "अपील" शब्द का अर्थ उच्च न्यायालय में अपील से है, न कि किसी एकल न्यायाधीश के लिए और उक्त अपील का अंतिम निपटान केवल उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि उस अपील के निपटारे में चाहे जो भी आंतरिक व्यवस्था हो, अंतिम निपटारे तक एक ही अपील होती है, यह तर्क प्रशंसनीय है, लेकिन इसे इस न्यायालय का समर्थन नहीं मिला है। इस न्यायालय में भारत संघ (यूओआई) बनाम मोहिन्द्रा सप्लाई कंपनी में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या भारत मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39(2) ने लेटर्स पेटेंट के तहत अपील का अधिकार छीन लिया है। उक्त अधिनियम की धारा 39(2) इस प्रकार है:

> "इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश के खिलाफ कोई द्वितीय अपील नहीं की जाएगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा या छीन नहीं लेगा।"

जैसा कि हमारे सामने तर्क दिया गया है, कि धारा के तहत दूसरी अपील एक वरिष्ठ न्यायालय में अपील को संदर्भित करती है, न कि "इंट्रा-कोर्ट" अपील के लिए और इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39(2)

एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के तहत अपील पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई नहीं की गई। इस न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति " द्वितीय अपील" में लेटर्स पेटेंट के तहत एक अपील शामिल है। यह निर्णय बताता है कि लेटर्स पेटेंट अपील मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर अपील का हिस्सा नहीं है, बल्कि एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक नई अपील है। इस न्यायालय में लाडली प्रसाद जयसवाल बनाम. करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड और अन्य में "तुरंत नीचे न्यायालय" संविधान के 133(1)(ए) में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को लिया गया। जहां जिला न्यायाधीश के फैसले को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पलट दिया. अधीनस्थ न्यायाधीश की अपील में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष एक पेटेंट अपील दायर की गई और उक्त खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की। प्रश्न यह उठा कि क्या एकल न्यायाधीश खंडपीठ के ठीक नीचे की अदालत थी। प्रत्यार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी, तुरंत नीचे के न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करता है और अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था इसलिए, उच्च न्यायालय एक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए संविधान के 133(1)(ए) के तहत सक्षम नहीं था। अपीलकर्ता ने यह आग्रह किया गया था कि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एकल न्यायाधीश

के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील उच्च न्यायालय के भीतर एक "घरेलू अपील" थी और यह तय करने में कि क्या अपील में खंडपीठ का फैसला लेटर्स पेटेंट के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले से तुरंत नीचे न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसके फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की गई थी। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभिव्यक्त "तुरंत नीचे न्यायालय" 133(1)(ए) का तात्पर्य उस न्यायालय से है जिसके निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है, चाहे ऐसा न्यायाधीश उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन कोई अन्य न्यायालय हो। यह देखा जाएगा कि यदि लेटर्स पेटेंट अपील केवल घरेलू व्यवस्था द्वारा जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध दायर अपील की निरंतरता थी, तो इस न्यायालय ने माना कि लेटर्स पेटेंट अपील में निर्णय पुष्टि का निर्णय नहीं था बल्कि जिला न्यायालय के फैसले को पलटने में से एक है। इसलिए, यह न्यायालय मानता है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निपटाई गई अपील और एकल न्यायाधीश के फैसले से उसकी डिवीजन बेंच तक की अपील अलग-अलग अपील हैं। इन निर्णयों के अलावा, सिद्धांत रूप में हमें अधिनियम की धारा 39(1) के तहत अपील और लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील को एक ही अपील के हिस्से से रखने का कोई औचित्य नहीं

दिखता है। वे कानून में और वास्तव में अलग-अलग अपीलें हैं - एक क़ानून द्वारा दी गई है और दूसरी लेटर्स पेटेंट द्वारा दी गई है। इसलिए, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि अधिनियम की धारा 39 में अभिव्यक्त "अपील" लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक लेटर्स पेटेंट अपील में ली गई है।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 39 उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत रूप से एक विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करती है और इसलिए, अपील में एकल न्यायाधीश का निर्णय खंड 10 के अर्थ में "निर्णय" नहीं है। लेटर पेटेंट इस दृष्टिकोण के समर्थन में, अन्य बातों के अलावा, राधा पाठक बनाम उपेन्द्र पटोवारी एआईआर 1962 गुवाहाटी.71 और पर भरोसा रखा गया था।हंसकुमार किशनचंद बनाम. भारतीय संघ (यूओआई),लेकिन, अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित धारा 39 की संरचना पर हमने जो विचार व्यक्त किया है, इस अपील में उस प्रश्न से निपटना आवश्यक नहीं है। यह नहीं समझा जाएगा कि हमने इस प्रश्न पर किसी न किसी रूप में अपनी राय व्यक्त की है।

परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गणेश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।